3 हमलावर और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हुए आत्मघाती हमलों में। बलूचिस्तान के लोरालाई जिले में स्थित पुलिस लाइंस के मुख्य द्वार पर यह हमला हुआ। इस हमले में चार पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं।

चुनावों में रूस की दखलअंदाजी पर सार्वजनिक बयान देंगे रॉबर्ट मुलर

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- विशेष वकील ने की थी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मास्को के दखल की जांच
- इसी जांच को लेकर 17 जुलाई को संसदीय समितियों के समक्ष होंगे पेश

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल मामले की जांच करने वाले विशेष वकील रॉबर्ट मुलर इस पर अब सार्वजनिक बयान देंगे और संसदीय समितियों के समक्ष गवाही देंगे।

सवाल-जवाब के क्रम में वह इन समितियों को बताएंगे कि साल 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने किस तरह से हस्तक्षेप किया था। संसदीय समिति में रॉबर्ट मुलर की पेशी का टीवी पर सजीव प्रसारण भी किए जाने की संभावना है। मुलर के इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप पर महाभियोग चलाने की फिर मांग उठ सकती है। मुलर ने अपनी जांच में ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम और रूस के बीच साठगांठ का कोई सुबूत नहीं पाया था, लेकिन ट्रंप को पूरी तरह से दोषमुक्त भी नहीं करार दिया था।

संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की न्याय और खुफिया मामलों की समितियों के प्रमुखों ने मंगलवार को बताया कि मुलर 17 जुलाई को पेश होंगे। प्रतिनिधि सभा में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है।

न्याय समिति के चेयरमैन जेरोल्ड नेडलर ने मुलर को लिखे पत्र में कहा, 'अमेरिकी जनता सीधे आप से आपके द्वारा की गई जांच और निष्कर्ष के बारे में जानने की हकदार है। हम कानूनी चिंताओं को दूर करने और आपके काम की पवित्रता की रक्षा के लिए साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि आप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसदीय समितियों के समक्ष पेश होंगे और सार्वजनिक बयान देंगे।'

रॉबर्ट मुलर। एपी

ट्रंप बोले, राष्ट्रपति का उत्पीड़न

संसदीय समितियों के समक्ष मुलर के पेश होने की खबर पर ट्रंप ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने महज दो शब्दों के ट्वीट में लिखा, 'राष्ट्रपति का उत्पीड़न।'

अप्रैल में मुलर ने सौंपी थी जांच रिपोर्ट

एफबीआइ के निदेशक रह चुके मुलर ने करीब 22 माह की जांच के बाद गत अप्रैल में अपनी 448 पेज की रिपोर्ट अभियोजन दफ्तर को सौंपी थी। इसके बाद यह रिपोर्ट संसद को देने के साथ सार्वजनिक की गई थी।

तालिबान हमले में अमेरिका के दो सैनिकों की मौत

काबुल, एएफपी: अफगानिस्तान के दक्षिणी वारदाक प्रांत में बुधवार को तालिबान आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में दो अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने घटना की पुष्टि की है। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए तालिबान ने कहा कि घटना को सयेद अबाद जिले में अंजाम दिया गया।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो के अफगानिस्तान दौरे के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि तालिबान आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। अफगानिस्तान में शांति के लिए तालिबान के साथ चल रही बातचीत को लेकर पोंपियो ने काबुल दौरे के दौरान आशा व्यक्त की थी कि इस साल एक सितंबर से पहले समझौता हो जाना चाहिए। अमेरिकी प्रतिनिधि और तालिबान के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दोहा में दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत इसी शनिवार को शुरू होनी है। पिछली शांतिवर्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला है। अफगानिस्तान में आतंकी हमलों में इस साल अभी तक नौ अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 12 था।

समूह-20 में होने वाली तीन बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- डोनाल्ड ट्रंप, शी चिनफिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी बैठक
- समूह-20 बैठक में हिस्सा लेने बुधवार शाम जापान रवाना हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी। फाइल

प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके नरेंद्र मोदी की विशेष कूटनीति का आगाज गुरुवार से जापान के शहर ओसाका से होगा। ओसाका में 27 से 29 जून, 2019 तक समूह-20 देशों की बैठक होने वाली है। बुधवार देर शाम मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। वैसे तो मोदी से मुलाकात का आग्रह लगभग तमाम देशों से आया था लेकिन अभी तक विदेश मंत्रालय ने आठ देशों के प्रमुखों के साथ भारतीय पीएम की द्विपक्षीय आधिकारिक मुलाकात का समय तय किया है। आठ द्विपक्षीय मुलाकातों के अलावा मोदी वहां तीन बहुपक्षीय मुलाकातों में हिस्सा लेंगे।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी जापान के पीएम शिंजो अबे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनकी त्रिपक्षीय बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक भी होनी तय है। इन तीन बहुपक्षीय बैठक के अलावा पीएम मोदी की आस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरीसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति तैयीप एर्डोगन, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सउदी अरब के प्रिंस सलमान समेत आठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी तय है। अन्य देशों का आग्रह भी है लेकिन समयाभाव की वजह से सभी को स्वीकार करना संभव नहीं हो पा रहा है। अन्य नेताओं के साथ अनौपचारिक मुलाकात होगी।

सनद रहे कि समूह-20 बैठक का आयोजन वर्ष 2007-08 के वैश्विक मंदी के बाद अमेरिका के आग्रह पर शुरू किया गया था ताकि वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर एक समग्र नीति बनाई जा सके। इस समूह ने ब्लैक मनी और आतंक के खिलाफ फंडिंग रोकने जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को पुख्ता करने का काम किया है। ओसाका में होने वाली बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों को लेकर विमर्श होगा।

न्यूज गैलरी

पाकिस्तान के पेशावर में बनेगा देश का पहला सिख स्कूल

पेशावर: पाकिस्तान के पेशावर शहर में देश के पहले सिख स्कूल की स्थापना शीघ्र की जाएगी। इसमें केवल सिख समुदाय के छात्र ही पढ़ाई कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार के प्रांतीय औकाफ विभाग ने पेशावर में स्कूल भवन के निर्माण को मंजूरी देते हुए 22 लाख रुपये का आवंटन भी कर दिया है। विभाग ने कहा, 'सिखों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने समुदाय के लिए अलग से स्कूल बनाने का आग्रह किया था।' एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सालाना बजट 2019-20 के तहत प्रांतीय सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 5.5 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इनमें 86 लाख रुपये अल्पसंख्यकों के त्योहारों के आयोजन के लिए हैं। (प्रेट्र)

कोस्टा रिका-पनामा सीमा पर भूकंप का झटका

सैन जोस: पनामा और कोस्टा रिका की सीमा पर मंगलवार की मध्य रात्रि के करीब भूकंप का जबरदस्त झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि भूकंप से लोगों के हताहत होने और नुकसान होने की आशंका है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र पनामा में प्रोग्रेसो शहर से लगभग दो किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। (एएफपी)

सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत को मिला समर्थन

कूटनीतिक जीत ▶ पाकिस्तान और चीन ने भी दिया भारत का साथ

यूएनएससी में 2021-22 के कार्यकाल में अस्थायी सदस्य रहेगा भारत

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में दो साल की अस्थायी सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है और विश्व मंच पर देश की बढ़ती साख को दिखाता है। भारत की कूटनीतिक गोलबंदी ऐसी थी कि पाकिस्तान और चीन को भी भारत की सदस्यता का समर्थन करना पड़ा। पंद्रह सदस्यीय परिषद में 2021-2022 के कार्यकाल के लिए पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव जून 2020 के आस-पास में होना है। इन सदस्यों का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने मंगलवार को ट्वीट किया, 'सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021/22 के दो साल के अस्थायी कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी का अनुमोदन सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र में किया। सभी 55 सदस्यों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद।'

सैयद अकबरुद्दीन। फाइल

इन देशों ने किया भारत का समर्थन: भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले 55 देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कुवैत, किर्गिस्तान, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल हैं।

दो साल के लिए पांच अस्थायी सदस्यों का होता है चयन: हर साल 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा दो साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के पांच अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। यूएनएससी की 10 अस्थायी सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय आधार पर किया गया है। अफ्रीका और एशिया के हिस्से में पांच जबकि पूर्वी यूरोप के हिस्से में एक, लातिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के हिस्से में दो, पश्चिमी यूरोप के हिस्से में दो सीटें हैं।

भारत पहले भी रह चुका है अस्थायी सदस्य

इससे पहले भारत 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और हाल ही में 2011-12 में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। इस महीने की शुरुआत में एस्तोनिया, नाइजर, सेंट विन्सेंट ऐंड द ग्रेनाडिन्स, ट्यूनिशिया और वियतनाम को दो साल के लिए यूएनएससी का सदस्य चुना गया है। इनका कार्यकाल 2020 से शुरू हो रहा है। सेंट विन्सेंट ऐंड द ग्रेनाडिन्स सुरक्षा परिषद में जगह पाने वाला सबसे छोटा देश है।

'आतंकवाद उद्योग' पाक को ठीक से नहीं चलने दे रहा

लंदन, प्रेट्र : पाकिस्तान में सरकार संरक्षित 'आतंकवाद उद्योग' उसे सामान्य पड़ोसी जैसा आचरण नहीं करने दे रहा। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन के निकट बकिंघमशायर में मनाए जा रहे ब्रिटेन-भारत सप्ताह की लीडर्स सम्मिट में कही। भारतीय विदेश मंत्री वीडियो लिंक के जरिये नई दिल्ली से समारोह को संबोधित कर रहे थे।

जयशंकर ने कहा कि विश्व बिरादरी खासकर ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करने के मामले में ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो काम कर रहा है-वह ब्रिटेन समेत बाकी की दुनिया पर भी असर डाल रहा है। विदेश मंत्री का आशय का पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कृत्य से था। जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के लिए आतंकवाद बड़े उद्योग जैसा है। जहां आतंकी पैदा होते हैं और फिर उनका इस्तेमाल पड़ोसियों के खिलाफ किया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जहां आतंकवाद को सरकार से इतना ज्यादा संरक्षण मिलता है। भारत को पाकिस्तान का यह स्वरूप स्वीकार नहीं है। ...और यह सोच रखने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। जयशंकर ने यह बात समारोह में पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही।

जयशंकर ने कहा, भारत ने पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाने के लिए उसे कारोबार के लिए सबसे उपयुक्त देश (एमएफएन) का दर्जा दिया लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, दक्षिण एशिया में दिलों को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और कारोबार से दूर रहने वाले रुख के चलते ऐसा नहीं हो सकता।

एस जयशंकर। फाइल

ब्रिटेन हमारे लिए हर तरह से खास

ब्रिटेन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यापार सहयोगी है। वह यूरोपीय यूनियन में रहे या नहीं रहे, हमारे लिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने के लिए जब भी और जिस रूप में मौका मिलेगा, हम उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।

अमेरिका-चीन ट्रेड वार से बाइबल महंगी चर्च हुए खफा

वाशिंगटन, प्रेट्र : चीन के साथ व्यापार संतुलन के नाम पर टैरिफ वार छेड़ कर बैठे ट्रंप से उनका मुख्य समर्थक वर्ग ही नाराज होता दिख रहा है। चीन से आने वाली वस्तुओं पर भारी-भरकम आयात शुल्क लगाने के फैसले का असर बाइबल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इससे चर्च ट्रंप से खफा बताए जा रहे हैं।

दुनिया की करीब आधी बाइबल चीन में छपती है। अमेरिका भी बाइबल के लिए काफी हद तक चीन से आयात पर ही निर्भर है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार के मोर्चे पर टकराव पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था। उस समय ट्रंप ने चीन से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात शुल्क लगा दिया था। अब तक ट्रंप चीन से आने वाली 250 अरब डॉलर की वस्तुओं पर 25 फीसद का आयात शुल्क लगा चुके हैं। बदले में चीन भी ऐसा ही कदम उठा रहा है।

अब ट्रंप ने छपी हुई वस्तुओं समेत चीन से आने वाली 300 अरब डॉलर की वस्तुओं पर आयात शुल्क की बात कही है। जानकारों का कहना है कि इससे धार्मिक समूहों, चर्चों, स्कूलों, मंत्रालयों और कई गैर-लाभकारी संस्थाओं पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिकी सांसद जोश हार्डर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ने बाइबल पर अतिरिक्त कर लगाने का विचार किया होगा, लेकिन चीन पर लगने वाले आयात शुल्क से इस पर भी असर पड़ेगा।' उन्होंने ट्रंप को खत लिखकर चीन से आने वाली बाइबल को आयात शुल्क के दायरे से बाहर रखने की अपील की है।

काम का बोझ खराब कर रहा ग्रामीण महिलाओं की सेहत

- ब्रिटेन के ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय ने भारतीय महिलाओं पर किया शोध
- महिलाएं घर के साथ ही खेतों में भी करती हैं काम
- नहीं मिलता है खुद और बच्चों की देखभाल का वक्त

लंदन, प्रेट्र : भारतीय महिलाओं पर पड़ने वाला काम का बोझ वह कारण है जिससे वे खुद शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं और उनके बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। यह बात ब्रिटेन के ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय (यूईए) के शोध में सामने आई है।

शोध के अनुसार भारतीय महिलाएं घरेलू कामकाज के साथ ही खेती में भी हाथ बंटाती हैं। यह स्थिति कमोबेश पूरे ग्रामीण भारत में है। इसका नतीजा होता है कि वे काम करते हुए ज्यादा थक जाती हैं। तमाम मौकों पर पुरुष जब काम के सिलसिले में शहर जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में महिलाओं को घर के काम के साथ खेती की भी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ऐसे में खाने-पीने और आराम करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है और वे जल्दी-जल्दी बीमार पड़ती हैं। इस दौरान जब वे मां बनती हैं तो बच्चा भी कमजोर पैदा होता है। इसके बाद नवजात शिशु भी पर्याप्त देखभाल के अभाव में कमजोर रहता है और विभिन्न रोगों का शिकार हो जाता है। यही कुपोषण की स्थिति उसके जीवन के लिए घातक साबित होती है। विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नित्या राव कहतीं हैं कि महिलाओं का खेत में काम करना उनके लिए घातक साबित होता है। वहां जाने-आने और काम करने के बाद वे घरेलू जिम्मेदारियों को ढंग से नहीं पूरा कर पाती हैं। दोहरी जिम्मेदारियां पूरी करने में वह अक्सर अपने और बच्चों के स्वास्थ्य में लापरवाही बरत जाती हैं और उसका खामियाजा उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।

शोध में महाराष्ट्र के वर्धा और ओड़िशा के कोरापुट जिलों के 12 गांवों की महिलाओं की दशा का अध्ययन किया गया है। इस इलाके में 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे औसत वजन से कम के पैदा होते हैं और आगे के जीवन में भी वे कुपोषण के शिकार रहते हैं।

प्रत्यर्पण कानून को लेकर प्रदर्शन

विवादित प्रत्यर्पण कानून को रद्द किए जाने के लिए चीन के राष्ट्रपति पर दबाव बनाने को सैकड़ों लोगों ने बुधवार को हांगकांग स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और यूरोपीय यूनियन के नेता अगले सप्ताह जापान में होने वाले समूह-20 सम्मलेन के दौरान इस विवादित कानून का मामला चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के सम्मुख उठाएं। हालांकि देशव्यापी प्रदर्शन के बाद इस कानून को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की गई थी। मगर लोगों का गुस्सा अब भी शांत नही हुआ है। एपी

उत्तर कोरिया बोला, अमेरिका के सामने नहीं करेंगे सरेंडर

सियोल, एपी : उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह प्रतिबंधों के चलते अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। उसने यह आरोप भी लगाया कि वाशिंगटन उसे घुटनों के बल लाने का प्रयास कर रहा है। उत्तर कोरिया का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था। दोनों की दो बार शिखर वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन गत फरवरी में वियतनाम में दूसरी शिखर बेनतीजा समाप्त हुई थी। उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण के बदले प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी। यह वार्ता विफल होने के बाद से ही दोनों देशों में गतिरोध बना हुआ है। ट्रंप और किम की पहली शिखर वार्ता गत वर्ष जून में सिंगापुर में हुई थी।

उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा, 'अगर कोई हमारी संप्रभुता को रौंदने की हिम्मत करेगा, तो हम अपनी रक्षा के लिए सैन्य ताकत दिखाने से गुरेज नहीं करेंगे।' मंत्रालय ने आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका ने दुश्मनी वाला रवैया बरकरार रखा है। इसका उदाहरण अमेरिका की हालिया रिपोर्ट से मिलता है। यह रिपोर्ट उत्तर कोरिया में कथित मानव तस्करी और धार्मिक क्रिया-कलापों पर सख्ती पर आधारित थी।

पोंपियो पर भी साधा निशाना: उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोंपियो पर निशाना साधते हुए कहा कि वह परमाणु वार्ता में अवरोध हैं। पोंपियो के हालिया बयान उत्तर कोरिया के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण कृत्यों को दर्शाते हैं।

ट्रंप-किम की तीसरी वार्ता के प्रयास भी

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने बुधवार को कहा कि ट्रंप और किम की तीसरी शिखर वार्ता को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका और उत्तर कोरिया के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। ट्रंप और किम दोबारा मुलाकात करने के इच्छुक हैं। बता दें कि गत फरवरी में ट्रंप और किम की शिखर वार्ता विफल होने के बाद से दोनों देशों में कोई सार्वजनिक बैठक नहीं हुई है। यह प्रयास पर्दे के पीछे से चल रहा है।

मुसीबत

यात्रियों ने टूर ऑपरेटर के कुप्रबंधन को जिम्मेदार बताया, वहीं टूर ऑपरेटर खराब मौसम को इस हालात का कारण बता रहे हैं

नेपाल में फंसे 200 कैलास मानसरोवर तीर्थयात्री

काठमांडू, प्रेट्र : कैलास मानसरोवर यात्रा से वापस लौट रहे करीब 200 तीर्थयात्री नेपाल में फंस गए हैं। यात्रियों ने इसके लिए टूर ऑपरेटरों के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है तो टूर ऑपरेटर हालात के लिए खराब मौसम को कारण बता रहे हैं।

हर साल सैकड़ों भारतीय तीर्थयात्री नेपाल होते हुए चीन में स्थित कैलास मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। इनमें हिंदुओं के अतिरिक्त जैन और बौद्ध तीर्थयात्री भी होते हैं। इन दोनों धर्मों में भी कैलास पर्वत का बड़ा महत्व है। तीर्थयात्री इस समय चीन सीमा के निकट नेपाल के हिलसा कस्बे में फंसे हुए हैं। यहां पर वे तिब्बत के बुरांग से आए हैं। हिलसा से उन्हें हेलीकॉप्टर से सिमिकोट जाना है और वहां से नेपालगंज। तीर्थयात्रियों के जत्थे में शामिल पंकज भटनागर (40) ने बताया कि जब वे हिलसा पहुंचे तो उन्हें वहां पर रुकने के लिए कहा गया। लेकिन हिलसा के होटल और गेस्ट हाउस में पहले से ही भरे हुए थे।

उनमें कैलास मानसरोवर से लौटे तीर्थयात्री थे, जो टूर ऑपरेटर के कुप्रबंधन के चलते वहां रुके हुए थे। पंजाब के डेरा बस्सी के रहने वाले भटनागर ने बताया कि हिलसा में हो रही बारिश ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, वे कस्बे में फंसकर रह गए हैं। गुरुग्राम से आए मयंक अग्रवाल के अनुसार टूर ऑपरेटर का ध्यान केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर होता है, वे उनके लिए सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देते। इसी का नतीजा है कि खाने और ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था के बगैर यात्री परेशान होने के लिए विवश हैं। जबकि टूर ऑपरेटर का कहना है कि खराब मौसम के कारण हिलसा और सिमिकोट के बीच की हेलीकॉप्टर सेवा ठप है, इससे यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा स्थित कंपनी से जुड़े यतीश कुमार के अनुसार मौसम में सुधार होते ही यात्रियों को रवाना करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

पाक ने 58 श्रद्धालुओं को नहीं दिया वीजा

जागरण संवाददाता, अमृतसर

गुरुद्वारा डेहरा साहिब लाहौर में शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी पर जाने वाले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के जत्थे के 58 श्रद्धालुओं को इस बार पाकिस्तान सरकार ने वीजा नहीं दिया है। जत्था गुरुवार को रवाना होगा।

एसजीपीसी ने जत्थे में जाने के लिए 282 श्रद्धालुओं के पासपोर्ट पाक दूतावास को दिए थे। पाक दूतावास ने सिर्फ 224 श्रद्धालुओं को ही वीजा दिया है। एसजीपीसी के मुख्य सचिव डॉ. रूप सिह ने बताया कि श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व ननकाना साहिब में मनाने के लिए पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी बात की जाएगी, ताकि इन कार्यक्रमों के लिए एसजीपीसी भी सहयोग दे सके।

जत्था गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अबदाल, गुरुद्वारा ननकाना साहिब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा डेहरा साहिब, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब व गुरुद्वारा रोड़ी साहिब के दर्शन करेगा। 29 जून को गुरुद्वारा डेहरा साहिब में महाराजा रणजीत सिंह की बरसी आयोजित की जाएगी। 6 जुलाई को श्रद्धालुओं का यह जत्था भारत वापस आएगा।

अमेरिकी दूत सैम ब्राउनबैक को महात्मा गांधी पुरस्कार

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी विदेश मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के राजदूत सैम ब्राउनबैक को हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार उन्हें विश्व के अनेक देशों में धार्मिक बहुलतावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। इस दिशा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और मलेशिया में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ब्राउनबैक द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई।

वाशिंगटन के कैपिटल हिल में आयोजित अपने 16वें वार्षिक समारोह के दौरान एचएएफ ने ब्राउनबैक की सराहना करते हुए कहा कि कई देशों में असुरक्षा का सामना कर रहे हिंदुओं की दशा सुधारने को लेकर उन्होंने अहम प्रयास किए। इससे विश्वभर में मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को बल मिला। इस मौके पर ब्राउनबैक ने कहा कि हरेक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का दायित्व होता है।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के राजदूत सैम ब्राउनबैक (फाइल फोटो)। एपी

समारोह के दौरान एचएएफ ने अमेरिकी सांसद ब्रैड शरमैन को फ्रेंड ऑफ द कम्यूनिटी अवार्ड से सम्मानित किया। अमेरिकी संसद में शरमैन द्वारा आवाज बुलंद किए जाने के बाद ही पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जा सका।

फेसबुक भड़काऊ भाषण के संदिग्धों का डाटा फ्रांसीसी कोर्ट को देगा

पेरिस, रायटर : फेसबुक भड़काऊ भाषण के फ्रांसीसी संदिग्धों की पहचान से संबंधित डाटा फ्रांस की अदालत को देने के लिए राजी हो गया है। फेसबुक दुनिया के किसी देश में पहली बार ऐसा करने जा रहा है। फ्रांस के डिजिटल अफेयर्स मंत्री सेड्रिक ओ ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

'फेसबुक' ने यह फैसला कंपनी के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के बीच कई बैठकों के बाद लिया है। दरअसल, मैक्रों भड़काऊ भाषण और गलत सूचनाओं के ऑनलाइन प्रसार के नियमन में अग्रणी भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। 'फेसबुक' अभी तक आतंकी हमलों और हिंसक गतिविधियों के मामलों में आइपी एड्रेस और संदिग्धों से संबंधित डाटा मुहैया कराने में फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था के साथ सहयोग करता रहा है। लेकिन 'फेसबुक' के वैश्विक मामलों के प्रमुख निक क्लेग और सेड्रिक ओ के बीच बैठक के बाद भड़काऊ भाषण के मामलों में भी सहयोग करने का फैसला किया।